Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 19, Issue No. 5, October-2022, ISSN 2230-7540

1947 के बाद के भारत में दलित आंदोलन

डॉ० वन्दना शर्मा*

असिस्टेंट प्रोफेसर-इतिहास, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फतेहाबाद, आगरा (उ०प्र०)

सार - 1947 के बाद के भारत में दलित आंदोलन एक शक्तिशाली सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य दलित समुदाय द्वारा सदियों से झेले जा रहे उत्पीड़न को संबोधित करना है। बी.आर. अम्बेडकर जैसी प्रमुख हस्तियों के नेतृत्व में, इस आंदोलन ने दलितों के अधिकारों, सम्मान और सामाजिक समावेशन के लिए लड़ाई लड़ी है। इसके परिणामस्वरूप संवैधानिक सुरक्षा उपाय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और जागरूकता बढ़ी है, फिर भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिससे यह सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक सतत संघर्ष बन गया है। दलित आंदोलन की विरासत जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता की याद दिलाती है।

खोजशब्द - आंदोलन, भारत

----------X----------

परिचय

1947 के बाद के भारत में दलित आंदोलन एक सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक संघर्ष है, जिसका नेतृत्व दलित समुदाय के सदस्यों ने किया, जिन्हें पहले हिंदू जाति व्यवस्था के भीतर "अछूत" के रूप में जाना जाता था। यह भारत में सदियों से व्याप्त गहरे सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा जिसे दलितों ने सहन किया था। वर्ष 1947 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की आजादी और उसके बाद एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाने का प्रतीक है जो सैद्धांतिक रूप से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है।(. अम्बेडकर, बी.आर. (1936) "दलित" शब्द संस्कृत शब्द "दलित" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "उत्पीड़ित" या "दलित"। इसे बी.आर. अम्बेडकर जैसे नेताओं द्वारा अपनाया गया था, जिन्होंने इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले विविध समुदायों को सशक्त बनाने और एकजुट करने के लिए दलित आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1947 के बाद के दलित आंदोलन को कई प्रमुख पहलुओं में समझा जा सकता है:

अम्बेडकर का नेतृत्व: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, एक दलित विद्वान, न्यायविद् और राजनीतिज्ञ, 1947 के बाद के दलित आंदोलन में एक केंद्रीय व्यक्ति थे। वह भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे और उन्होंने दलितों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने दलितों को सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के साधन के रूप में शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रत्येक समाज में वर्ग विभाजन मौजूद होता है जो निम्नतर श्रेष्ठ स्थिति, अमीर गरीब, दास स्वामी, श्रमिक पूंजीपति, ब्राह्मण दलित आदि पर आधारित होता है, एक प्रमुख वर्ग दूसरे अधीनस्थ वर्ग का शोषण करता है जैसा कि हमने इतिहास से सीखा है। भारत के इतिहास में ये अधीनस्थ वर्ग आमतौर पर महिलाएं, निचली जातियां, दलित, आदिवासी, गरीब लोग आदि हैं। इन वर्गों का सदियों से राजनीतिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि माध्यमों से शोषण किया जाता रहा है। दलित वे लोग हैं जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से दबाए जाते हैं। इन लोगों को अछूत नहीं माना जाता है, ये लोग गांवों के बाहर और शहरों में कम वेतन वाले व्यवसाय पर निर्भर होकर रहने को मजबूर हैं, सड़कों पर झाड़ू लगाना, नालियों की सफाई करना, शहरों में मजदूरी करना, इन्हें इंसान का पूरा दर्जा नहीं दिया गया है। पारंपरिक हिंदू आधारित जाति व्यवस्था से उनका सदियों से शोषण किया गया है, जहां ब्राह्मण उनका शोषण करते हैं। दलित (निचली जाति)

www.ignited.in

अपनी जाति नहीं बदल सकते, यह भारत में पदानुक्रमित है, ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण होते हैं और दलित हमेशा दलित होते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दलितों पर अत्याचार होता है; इस पुराने रिवाज के कारण उन्हें अपमानजनक और गंभीर गरीबी की स्थिति में रहना पड़ता है। 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत ने लोकतंत्र को अपनाया लेकिन दलित अभी भी क्रूरता की स्थिति में रहते हैं, उन्हें उस मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है जहां ब्राह्मण जाते हैं, उन्हें कक्षा कक्ष में सीखने की अनुमति नहीं है जहां ब्राह्मण भी बैठते हैं। इन सभी बातों पर, जिनकी हम चर्चा करते हैं, आजादी के बाद एक आंदोलन खड़ा हुआ जो दलित आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह दलितों पर अत्याचार, ब्राह्मणों की लंबे समय से चली आ रही क्रूरता, दलितों का अपमान, दलितों की असमानता, अस्पृश्यता आदि के खिलाफ है। यह आंदोलन सीधे तौर पर सड़कों, गांवों, शहरों, सड़कों पर विरोध आंदोलन नहीं है, यह भाषण के माध्यम से एक आंदोलन है, लेख, नाटक, गीत, सम्मेलन आदि लिखना।

दलित: अवधारणा

दलित पारंपरिक रूप से निम्न वर्ग माने जाने वाले लोगों के समूह के लिए एक स्व-पदनाम है। वे पूरे दक्षिण एशिया में कई जाति समूहों की मिश्रित आबादी हैं और विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं। परंपरागत रूप से, चार प्रमुख जातियाँ हैं (कई उप-श्रेणियों में विभाजित) और लोगों की एक श्रेणी जो जाति व्यवस्था से बाहर हैं - दलित। (अंधारी जाह्न, (2008) दलित शब्द - जिसका शाब्दिक अर्थ है 'उत्पीड़ित' या टूटा हुआ', आमतौर पर उन लोगों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें कभी 'अछूत' के रूप में जाना जाता था, जो कि चार गुना हिंदू वर्ण व्यवस्था के बाहर की जातियों से संबंधित थे। वे अंत्यज हैं, यानी वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं (मेहरोत्रा, एन.डी.)। दलितों को कई अन्य नामों से भी बुलाया जाता है: दस्यु, दास, अतिशूद्र, पंचमा, तिरुकुलत्तर, आदिकर्नाटक, आदि द्रविड़, अनुसूचित जाति (एससी) आदि, लेकिन अंबेडकर ने उन्हें "दलित वर्ग" कहा, दलित समुदाय के भीतर, कई विभाजन हैं उपजातियों में. दलितों को चमड़े का काम करने वाले, सड़क पर सफ़ाई करने वाले, मोची, कृषि श्रमिक और मैनुअल "मैला ढोने वाले" में विभाजित किया गया है।

बाद वाले समूह को निम्न में से सबसे निचला समूह माना जाता है और आधिकारिक तौर पर अनुमान लगाया गया है कि इसकी संख्या दस लाख है, जो परंपरागत रूप से गांव की कब्रें खोदने, मृत जानवरों का निपटान करने और मानव मल को साफ करने के लिए जिम्मेदार हैं। दलित कार्यबल का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में है। देश के चालीस करोड़ बंधुआ मजदूर लोगों में से अधिकांश दलित हैं। ये नौकरियाँ शायद ही कभी दलितों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने या अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पर्याप्त आय प्रदान करती हैं। परिणामस्वरूप, कई दलित गरीब, अशिक्षित और अशिक्षित हैं।

व्यापक दृष्टिकोण यह है कि 'दलित' शब्द किसी जाति से संबंधित नहीं है; इसमें सभी जातियों के गरीब, शोषित और श्रमिक शामिल हैं; और जो समाज में ईमानदारी से काम करने में असमर्थ हैं उन्हें दलित माना जाता है।

"जो लोग सदियों से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से शोषित हैं, मानव समाज में रहने में असमर्थ हैं, गाँव के बाहर निचले स्तर के व्यवसाय पर निर्भर हैं, और अपना नाम बताने में असमर्थ हैं, वे 'अछूत' के रूप में रहते हैं। दलित माना जाता है"। वर्तमान दलित पहचान की यात्रा ने 'अछूत', 'अदृश्य', 'अगम्य', 'काली जाति', 'अति-शूद्र', 'हरिजन', 'उदास' के रूप में पहचाने जाने से एक लंबा सफर तय किया है। जाति', 'आदिवासी' और 'अनुसूचित जाति'। इनमें से किसी ने भी अर्थ में वास्तविक परिवर्तन नहीं लाया है, क्योंकि दलित इस धारणा से बंधे हुए हैं कि दिन के अंत में, हम 'अलग', 'पृथक' और 'बहिष्कृत' हैं।

दलित आंदोलन

यह संभव है कि दलित आंदोलन (जिसे यहां जातिगत भेदभाव से लड़ने के लिए पूर्व अछूत लोगों के ठोस प्रयास के रूप में समझा जाता है) की उत्पत्ति औपनिवेशिक युग से पहले नहीं हो सकती। हालाँकि, इसे जाति के इतिहास के साथ सह-अस्तित्व में रहना पड़ा, खासकर ब्राह्मणवादी विचारधारा की प्रबलता के खिलाफ निचली जातियों की लड़ाई के संदर्भ में। इसे भारत की कठोर जाति व्यवस्था द्वारा थोपी गई अन्यायपूर्ण आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ लंबे समय तक मौन प्रतिरोध की परिणति के रूप में भी देखा जा सकता है।(कैलीकोग्लू मेलिह रुस्तू (2005)

जन आंदोलन, या जमीनी स्तर की पहल जो मोटे तौर पर समकालिक थीं, समकालीन दलित आंदोलन की उत्पत्ति थीं। इन आंदोलनों ने दलितों को ईसाई धर्म, इस्लाम और

सिख धर्म सहित अन्य धर्मों में परिवर्तित होते देखा। अधिकांश भ्रम इन आंदोलनों के आसपास व्यापक बहस से उत्पन्न होता है। ये परिवर्तन एक सामाजिक आंदोलन के रूप में योग्य हैं या नहीं, यह बहस का विषय है, क्योंकि बाद वाले को तकनीकी रूप से सामाजिक परिवर्तन के एक सामान्य उद्देश्य की दिशा में काम करने वाले संगठन की आवश्यकता होती है। जाति व्यवस्था की अवज्ञा करना और नया धर्म अपनाना कम से कम व्यक्तिगत स्तर पर विद्रोह की भावना प्रदर्शित करता है। भूमि संघर्ष जैसी दलित लड़ाइयों पर शोध से इस समूह के बारे में आम गलतफहमियों को दूर करने में मदद मिल सकती है। दलितों द्वारा भूमि पुनर्ग्रहण की लड़ाई, जो पहले दूरदराज के गांवों में छोटे समूहों में संगठित थी, अब क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर काफी विस्तारित हो गई है।

स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही, भारत में राजनीतिक नेता गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित थे। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, देश के गरीबों और राजनीतिक रूप से वंचित नागरिकों की मदद के लिए संवैधानिक प्रावधान लागू किए गए, जो ऐतिहासिक रूप से विभिन्न प्रकार के सामाजिक और आर्थिक अन्याय से पीड़ित थे। स्वतंत्र भारत की सरकार ने गरीबों के लिए सुरक्षा को संविधान में शामिल किया। 1947 में यह निर्णय दिया गया कि अस्पृश्यता कानून के विरुद्ध है।

मंडल आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद वी.पी. सिंह सरकार ने "अन्य पिछड़ा वर्ग" (जो कुल जनसंख्या का 27 प्रतिशत है) के रूप में पहचाने जाने वाले जनसांख्यिकीय को आरक्षण के दायरे में लाया गया था। विधानमंडलों और सामाजिक सेवाओं और सहायता कार्यक्रमों जैसे सरकारी संस्थानों तक अधिक पहुंच प्रदान किए जाने के बाद वे आगे बढ़े। अम्बेडकर के समय में, रिपब्लिकन पार्टी "दलित" राजनीति का प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी मृत्यु के बाद नये साहित्यिक आंदोलन और दलित पैंथर्स की राजनीति का उदय हुआ। हालाँकि, यह अघोषित बहुमत की आवाज़ थी।

समावेशन के लिए परिवर्तन

जाति व्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कोई कैसे काम कर सकता है? केवल स्वयं के पूर्ण कायापलट से ही यह संभव है। 'स्पृश्य' और 'अस्पृश्य' या 'उच्च' और 'गरीब' के रूप में जाति-आधारित पहचान कायम है क्योंकि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में उनका मूल्य बना हुआ है। यह महसूस करना कि जाति व्यवस्था व्यर्थ है, इसे बदलने की दिशा में पहला कदम है।(दास, नंदिता (2012)) इसलिए, परिवर्तन से गुजरने के लिए, किसी को न केवल एक, बल्कि अपनी दोनों पहचानों को त्यागना होगा, चाहे वे 'स्पृश्य' हों या 'अछूत'। केवल अगर कोई आश्वस्त हो कि दोनों प्रणालियाँ स्वाभाविक रूप से मानवता के लिए हानिकारक हैं तो यह संभव होगा। हालाँकि, निर्णय कभी भी सरल नहीं होता है, क्योंकि पारस्परिक संबंध एक प्राचीन लेकिन नव आकार की सामाजिक व्यवस्था (जाति) पर आधारित होते हैं। आधुनिकीकरण की दिशा में प्रगति और अवसर जाति के अधीन हैं। फिर, 'आधुनिकता' एक सापेक्ष शब्द है, जो विकास के विभिन्न चरणों के बीच बदलता रहता है और लगातार प्रतिस्पर्धी ताकतों को शामिल करता है। इसलिए, 'गतिशीलता' और 'भागीदारी' को बाहरी कारकों द्वारा आकार दिया जा सकता है या विफल किया जा सकता है।

चूंकि दलितों ने इतना उत्पीड़न सहा है, इसलिए वे हमेशा अपनेपन और उद्देश्य की तलाश में रहते हैं जो उनके जीवन को और अधिक सहनीय बना सके। क्योंकि उन्हें चिंता है कि अगर वे अपनी अमानवीय पहचान से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे तो उनकी पाखंडी वास्तविकता नष्ट हो सकती है, "स्पृश्य" दिमाग ऐसा करने के लिए कम प्रेरित होते हैं। प्रभावी होने के लिए, परिवर्तन गरिमा और मूल्य की ओर एक यात्रा होनी चाहिए जो समान विचारधारा वाले अन्य लोगों को आकर्षित और प्रेरित करे। "दलित" शब्द को जब "समानता" को महत्व देने वाले लोगों द्वारा एक नैतिक रुख के रूप में अपनाया और आत्मसात किया जाता है, तो यह इस प्रक्रिया में एक जबरदस्त कदम है।(इलियट, कैरोलिन एम. (1986) इसलिए, दलित वे लोग हैं जो मानते हैं कि सभी लोगों को समान बनाया गया है, जो दूसरों के साथ उसी सम्मान के साथ व्यवहार करने का प्रयास करते हैं जैसा वे चाहते हैं कि उनके साथ व्यवहार किया जाए, और जो सक्रिय रूप से किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध करते हैं। निष्कर्षतः, इस तथ्य के कारण कि एक व्यवस्था के रूप में 'जाति' एक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है, एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें कानून का उपयोग, जन लामबंदी, जागरूकता जैसी रणनीतियाँ शामिल हैं। अधिकार, मानवाधिकारों का वैश्वीकरण, भूमि सुधार, सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम, शिक्षा, महिला नेतृत्व और आध्यात्मिक प्रवचन का पुनर्निर्माण।

दलित आंदोलन के प्रमुख कारण

www.ignited.in

सहस्राब्दियों के दौरान भारत की ऊंची जातियों की बर्बर कार्रवाइयों ने उस दुश्मनी को बढ़ावा दिया है जिसने दलित आंदोलन को जन्म दिया है। दलितों को दास की भूमिका में धकेल दिया गया और उन्हें शिक्षा और उन्नति के अवसरों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया क्योंकि उन्हें निचली जाति माना जाता था। श्रम विभाजन के परिणामस्वरूप असमानता और शोषण पनपा, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों का विभाजन हुआ। जाति व्यवस्था के कारण, दलित समुदाय एक संक्रामक स्थिति में बदल गए जिसमें नौकरियाँ जातियाँ बन गईं।(हंस, वी. बेसिल (2010) सहस्राब्दियों से दलितों को फर्श साफ करने और सेप्टिक टैंक साफ करने जैसी निम्न दर्जे की नौकरियों में धकेल दिया गया है। चूंकि वे हिंदू समुदायों में रहते थे इसलिए वे अन्य जनजातियों की तरह भौगोलिक रूप से अलग-थलग नहीं थे। उन्हें बस्तियों के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि ब्राह्मणों ने केंद्र में निवास करना शुरू कर दिया। उन्हें न केवल मुख्य भूमि पर किसी को छूने की मनाही थी, बल्कि वे उचित ढंग से कपड़े भी नहीं पहन सकते थे या सज-धज भी नहीं सकते थे। इन अपराधों के शिकार अक्सर वे लोग होते थे जो एक विशेष आस्था को मानते थे। इसके अलावा, देवदासी प्रथा के तहत, जो दलित अनजाने में कोई मंत्र सुन लेता था, उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाता था। जनता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए शिक्षा पर एकाधिकार कर लिया गया। अस्पृश्यता, सबसे अमानवीय प्रथा, ने दलितों को भयावह परिस्थितियों को सहने के लिए मजबूर किया। परिणामस्वरूप, दलितों ने ब्राह्मणवाद की अंतर्निहित क्रूर प्रथाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करना शुरू कर दिया है।(हिरेगौदर, जी.सी. (2007) भारत में, दलितों ने उचित उपचार की मांग करके अपना अभियान शुरू किया। हालाँकि दलित आंदोलन वास्तव में आज़ादी के बाद शुरू हुआ, लेकिन इसकी उत्पत्ति वैदिक युग में मानी जा सकती है। इसने पहले श्रमणों और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष को जन्म दिया और बाद में भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। वर्तमान दलित आंदोलन की जड़ें पश्चिमी भाषाओं की शुरूआत और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से मानी जा सकती हैं, इन दोनों ने दलितों के बीच समानता और स्वतंत्रता के विचारों को फैलाने में मदद की। जब क्रोध को तर्क के साथ जोड़ दिया गया, तो दलित मन ने ब्राह्मणवाद के दुरुपयोग के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया।

दलित आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य हाशिये पर पड़े समुदायों को शेष समाज से जुड़ने में मदद करना था। वे सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के संदर्भ में एक सामाजिक वर्ग की दूसरे से श्रेष्ठता और बहिष्कार के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थे।

शिक्षित दलित समुदाय गरीबी, भेदभाव और उच्च जातियों के उत्पीड़न के अपने अनुभवों के बारे में खुल कर बताता है। जनगणना अभियान (जाति को परिभाषित करने की ब्रिटिश रणनीति) ने उन्हें फूट डालो और राज करो की रणनीति के हिस्से के रूप में मजबूत किया। इसने जातिगत लामबंदी के माध्यम से सामाजिक श्रेष्ठता के दावे करने का मार्ग प्रशस्त किया।

जानकारी तक पहुंच बढ़ने से नए सहयोग की सुविधा मिली, और शिक्षा, प्रशासन और कानून के शासन में सुधारों ने खेल के मैदान को समतल करने और पहले से आर्थिक सफलता से बाहर रखे गए लोगों के लिए उन्नति की बाधाओं को तोड़ने में मदद की।

इन सभी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप पूर्व में कलंकित समूहों की स्थिति में सुधार हुआ। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले और केरल में श्री नारायण गुरु दोनों ने सामाजिक सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिन्होंने जातिगत विशेषाधिकार पर सवाल उठाया।

जब गांधीजी ने अस्पृश्यता उन्मूलन को राष्ट्रीय उद्देश्य में शामिल किया, तब वर्कोम और गुरुवयूर सत्याग्रह जैसे प्रमुख अभियान और लड़ाइयाँ आयोजित की गईं। गांधीजी का लक्ष्य उच्च जाति को अस्पृश्यता की अनुचितता के बारे में बताना था।(मेहरोत्रा, निलिका (2012)) 1920 के दशक में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर दलित वर्गों के बीच एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। 1942 में उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की। इसके अलावा, वह अनुसूचित जाति के लिए बेहतर उपचार सुनिश्चित करने की उम्मीद में औपनिवेशिक प्राधिकरण के साथ काम करता है। अखिल भारतीय एस.सी. महासंघ के उम्मीदवार भी चुनाव में उतरे, लेकिन वे कांग्रेस से बुरी तरह हार गए। क्षेत्रीय शाखाएँ भी थीं, जैसे पंजाब में आदि धर्म, उत्तर प्रदेश में आदि हिंदी और बंगाल में नमश्वेदास।

दलित साहित्यिक आंदोलन

ऐसे समय में जब अन्य विकल्प अनुपलब्ध थे, कलम ही दलितों के लिए संचार का एकमात्र माध्यम था। प्रभावशाली ब्राह्मण अभिजात वर्ग ने सभी प्रेस आउटलेट्स को नियंत्रित किया। चूँकि ब्राह्मण कभी भी दलित आवाज़ को व्यक्त नहीं होने देंगे - यह उनके अस्तित्व के लिए

ख़तरा होगा - दलितों ने अपनी पत्रिका शुरू की और अपने स्वयं के अनुभवों को संप्रेषित करना शुरू कर दिया।

मुक्ति आंदोलन के दौरान ही दलित दृष्टिकोण से लिखी गई दलित साहित्य की पहली रचनाएँ सामने आईं। इसके बाद, दलित पैंथर्स उभरे, और उनके साथ दलितों के उत्पीड़न के बारे में ढेर सारी कविताएँ और कहानियाँ आईं, जिनकी उत्पत्ति वेदों और स्मृतियों के प्रामाणिक ग्रंथों में हुई थी। इस पूरे लेखन में दावा किया गया कि दलित आंदोलन न केवल ब्राह्मणों के खिलाफ संघर्ष है, बल्कि उन सभी के खिलाफ है जो दूसरों का शोषण करते हैं, चाहे वे ब्राह्मण हों या दलित।

दलित आंदोलन की गतिशीलता: संस्कृतिकरण

दलित आंदोलन की तकनीकें, विचार और दृष्टिकोण नेता दर नेता, स्थान दर स्थान और युग दर युग भिन्न थे। जाति व्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए कुछ प्रमुख दलित नेताओं द्वारा 'संस्कृतीकरण' की पद्धति का उपयोग किया गया था। उन्होंने ब्राह्मणों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया, अपने शाकाहार का अनुकरण करना, अपने माथे को चंदन के लेप से सजाना, पवित्र धागा पहनना आदि। यही कारण था कि दलित समुदाय के प्रमुख सदस्य, जैसे स्वामी थायक्कड़ (केरल), पंडी सुंदर लाई सागर (उत्तर) प्रदेश), मूलदास वैश्य (गुजरात), मून विठोबा रावजी पांडे (महाराष्ट्र) और अन्य ने प्रमुख जातियों के रीति-रिवाजों और मूल्यों का अनुकरण करने की कोशिश की। दलितों ने बराबरी की मान्यता की मांग के लिए ऊंची जाति के व्यवहार की नकल का इस्तेमाल किया।

आदि-हिन्दू आंदोलन

आदि-हिंदू आंदोलन इसलिए उभरा क्योंकि दलितों को चार-जाति वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया और उन्हें "बहिष्कृत" या "पंचमा" करार दिया गया। इस कारण से, दलित नेतृत्व में से कुछ ने दावा किया कि दलित भारत में हिंदुओं के आगमन से पहले से थे। आक्रमणकारी आर्यों या ब्राह्मणों ने हिंसा का उपयोग करके मूल आबादी पर अस्पृश्यता लागू की। उन्होंने तर्क दिया कि यदि हिंदू धर्म को छोड़ दिया जाए तो अस्पृश्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। उन राज्यों में दलितों ने खुद को आदि-आंध्र, आदि-कर्नाटक, आदि-द्रविड़, आदि-हिंदू और आदि-धर्मी कहना शुरू कर दिया। "अछूत" के रूप में अपनी स्थिति को समाप्त करने और अपनी नैतिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, कई दलितों ने धर्मांतरण का रास्ता चुना।

- **रूपांतरण**

विशेषकर केरल में बड़ी संख्या में दलितों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया। विशेषकर पंजाब में कुछ दलितों को सिख धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। उन्हें मजहबी, नामधारी, कबीर पंथी आदि के नाम से जाना जाता है। दलित भी बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। डॉ. अम्बेडकर ने 1956 में नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया।

- **सम्प्रदायों की खोज**

हिंदू धर्म के विरोध में कुछ दलित नेताओं ने अपने स्वयं के संप्रदाय या धर्म की स्थापना की। गुरु घासी दास (मप्र) ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की। गुरतिचंद ठाकुर (बंगाल) ने मतुआ संप्रदाय की स्थापना की। अय्यन काली (केरल) ने एसजेपीवाई (सधा जन परिपालन योगम) की स्थापना की और मंगू राम (पंजाब) ने आदि धरम की स्थापना की।

अंबेडकर की सक्रियता

सामाजिक और आर्थिक अन्याय से निपटने के लिए दलित समुदाय की ओर से राजनीतिक-संगठनात्मक प्रयास भी शुरू किए गए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में डॉ. अंबेडकर द्वारा की गई थी। उन्होंने शोषणकारी खोती प्रणाली को खत्म करने के लिए काम किया, जो महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में आम थी, साथ ही वेट्टी या महराकी प्रणाली (जो जाति के हिंदुओं को मुफ्त वंशानुगत सेवा प्रदान करती थी) को खत्म करने के लिए काम किया। स्थानीय सरकार में)। महारों को सेना में भर्ती करने के लिए उन्होंने समुदाय की ओर से सरकार से वकालत की। आख़िरकार उन्हें सफलता तब मिली जब 1941 में पहली महार रेजिमेंट की स्थापना हुई।

डॉ. अम्बेडकर ने लोकतंत्र के प्रसार के साथ-साथ सरकार और कानून निर्माण में उनकी उचित भागीदारी का आह्वान करते हुए दलितों के अधिकारों की वकालत की। केंद्रीय विधान सभा के हिस्से के रूप में, दलित वर्गों को 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार एक सीट की गारंटी दी गई थी। 'सांप्रदायिक पुरस्कार' पहली बार 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित किया गया था, जब रामसोय मैकडोनाल्ड प्रभारी थे। इस पुरस्कार द्वारा दलित वर्गों के लिए अलग मतदान अधिकार की कल्पना की गई।(राधे श्याम चौरसिया (2003) महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक

www.ignited.in

पुरस्कार के अपने विरोध की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध रूप से उपवास किया था, जिसमें उनका मानना था कि गरीबों और अन्य उत्पीड़ित समूहों को गलत तरीके से निशाना बनाया गया था। सितंबर 1932 में, पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, इस प्रकार संघर्ष समाप्त हो गया। इसने गारंटी दी कि वंचित समूहों को डाले गए वोटों की कुल संख्या का एक प्रतिशत सुनिश्चित किया जाएगा। अनुच्छेद 330 और 332 के तहत, भारतीय संविधान वर्तमान में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा और लोकसभा में एक निश्चित संख्या में सीटें आरक्षित करता है।

दलित आंदोलन का मूल कारण

महिलाएँ और दलित, भारतीय संस्कृति में सबसे अधिक उत्पीड़ित समूहों में से हैं, अक्सर व्यापक असमानता के प्रभावों को सबसे पहले महसूस करते हैं। यदि हम समय में काफी पीछे जाएं तो जाति व्यवस्था का विकास, जिसके कारण भारत में उत्पीड़ित वर्गों की अन्य श्रेणियों, महिलाओं, को अधीनता में लाया गया, को मूल कारण के रूप में देखा जा सकता है। स्थानीय आबादी के साथ हिंसक संघर्ष के बाद, मध्य पूर्व से भारत की यात्रा करने वाले आर्यों ने अंततः गंगा घाटी में अपना घर बनाया। ब्रज राजन मणि का तर्क है कि आर्य, जो अल्पसंख्यक हैं, कई रणनीतियों का उपयोग करके दलितों को हराने और भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम थे, जिनमें से सबसे आम "फूट डालो और शासन करो" थी। इतिहास बताता है कि आर्य लोग असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और कुशल थे। ब्राह्मण आज भी अपने प्राचीन अनुष्ठानों और संस्कारों का पालन करते हैं। उत्तर वैदिक युग में, जब ऋग्वेद का संकलन किया जा रहा था, पुरुष की दसवीं पुस्तक ने उनके देश में लोगों के अत्याचार के लिए आधार प्रदान किया। बाद में 5वीं शताब्दी में अछूत वर्ग की स्थापना हुई। यह दलितों के खिलाफ ब्राह्मण क्रूरता की उत्पत्ति का प्रतीक है, क्योंकि अस्पृश्यता की परंपरा संस्थागत हो गई है। ब्राह्मणों का किसी भी तरीके से सम्मान किया जाना चाहिए, भले ही वे अपराधों में भाग लेते हों, क्योंकि हिंदू लोगों की पवित्र पुस्तकें अस्पृश्यता के इस भयानक अपराध पर जोर देती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किताबें एक ऐसे समाज की पेशकश करती हैं जिसमें कुछ लोगों के साथ देवताओं जैसा व्यवहार किया जाता है जबकि अन्य के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। (सूत्रधार रुमान, (2014) आर्य-ब्राह्मण लोग, जो पहले से ही खुद को श्रेष्ठ मानते थे और जाति व्यवस्था स्थापित करके बाकी सभी को अपने स्थान पर रखना चाहते थे, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के विकास के लिए जिम्मेदार हैं जैसा कि हम आज जानते हैं। वास्तव में, उनका लक्ष्य श्रेष्ठता प्राप्त करना था ताकि वे सम्मानपूर्वक रह सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि अन्य जनजातियाँ उनके अधीन रहें। गेल ओमवेट की पुस्तक, दलित विज़न्स, दावा करती है कि हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद एक ही चीज़ हैं। वास्तव में, हिंदू धर्म के भेष में ब्राह्मणवाद भारत में ब्राह्मण जाति द्वारा बनाए गए भेदभावपूर्ण कानूनों को छिपाने के लिए बनाया गया था। यह हिंदू संस्कृति का आंतरिक हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसकी रचना ईश्वर ने नहीं, बल्कि ब्राह्मणों ने की है। वर्णाश्रम सिद्धांत के अनुसार, जो भारतीय जाति व्यवस्था का वर्णन करता है, प्रत्येक व्यक्ति पर धर्म, या हिंदू जाति व्यवस्था को बनाए रखने की मौलिक जिम्मेदारी है। कर्म और धर्म की हिंदू धार्मिक शिक्षाएँ जाति विचारधारा को आधार प्रदान करती हैं। धर्म बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है, और कर्म का तात्पर्य किसी व्यक्ति के पिछले जीवन में किए गए अच्छे कार्यों के लिए उचित पुरस्कार से है।

एक अन्य ब्राह्मण, कौटिल्य, मनु से सहमत थे कि जाति व्यवस्था को संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि यह भारतीय सभ्यता की नींव है और इसमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। "राष्ट्रपिता" गांधी ने भी यही बात कही: "परिवर्तन हमेशा अराजकता लाता है। " परिणामस्वरूप, ब्राह्मणों को समाज के शिखर पर और दलितों को आधार पर अपना स्थान बनाए रखना चाहिए।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः 1947 के बाद के भारत में दलित आंदोलन ऐतिहासिक उत्पीड़न के सामने लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की स्थायी भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा है। समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, आंदोलन हमें याद दिलाता है कि जाति-आधारित भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई एक सतत संघर्ष है। दलित आंदोलन की यात्रा यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करती है कि भारतीय संविधान में निहित सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांत सभी नागरिकों के लिए पूरी तरह से लागू हों, चाहे उनकी जाति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

संदर्भ

1. अम्बेडकर, बी.आर. (1936)। 'महात्मा' गांधी के उत्तर के साथ जाति का उन्मूलन, दलित साहित्य अकादमी, बैंगलोर, 1987 (पुनर्मुद्रण)।
2. अंधारी जाह्व, (2008) —भारत में दलित महिला आंदोलनः दलित महिला समिति॥ महिला अधिकार और विकास एसोसिएशन, पीपी.1-13।
3. कैलीकोग्लू मेलिह रुस्तू (2005) जाति व्यवस्था का परिवर्तन और दलित आंदोलन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल साइंस, पीपी. 56-72
4. दास, नंदिता (2012)। "एक महान पहचान", द वीक, वॉल्यूम। 30, संख्या 35, 26 अगस्त, पृ. 74.
5. इलियट, कैरोलिन एम. (1986)। प्रमुख जातियों के बीच जाति और गुटः आंध्र के रेड्डी और कम्मा। कोठारी में, रजनी (सं.), कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली, पुनर्मुद्रण
6. हंस, वी. बेसिल (2010)। भारत में समावेशी विकासः आयाम और दिशा। रासुरे में, के.ए. (सं.), समावेशी विकास चुनौतियां और अवसर, ऑक्सफोर्ड बुक कंपनी, जयपुर।
7. हिरेगौदर, जी.सी. (2007)। जिम्मेदार कार्यपालिका के माध्यम से सामाजिक न्याय का अम्बेडकर का दृष्टिकोण। विश्वनाथ (सं.) में, अम्बेडकर और समकालीन भारत में दलित, अकादमिक प्रकाशक, बैंगलोर
8. मेहरोत्रा, निलिका (2012)। "विकलांगता, लिंग और जातिः भारतीय अर्थव्यवस्था में सीमांतता, बहिष्करण और अवसर", महिला लिंक, वॉल्यूम। 18, संख्या 2, अप्रैल-जून, पृ. 5-8.
9. राधे श्याम चौरसिया (2003) —होस्टोरी ऑफ़ पॉलिटिकल थॉट॥ अटलांटिक पब्लिशर्स, पृष्ठ 156-180
10. सूत्रधार रुमान, (2014) "भारत में दलित आंदोलनः चार दलित साहित्य के प्रकाश में" आईओएसआर जर्नल ऑफ डेंटल एंड मेडिकल, पीपी 91-97।

Corresponding Author

डॉ० वन्दना शर्मा*

असिस्टेंट प्रोफेसर-इतिहास, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फतेहाबाद, आगरा (उ०प्र०)

www.ignited.in